



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-14092020-221711  
CG-DL-W-14092020-221711

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY  
साप्ताहिक  
WEEKLY

---

सं. 33]	नई दिल्ली, सितम्बर 6—सितम्बर 12, 2020, शनिवार/ भाद्र 15—भाद्र 21, 1942
No. 33]	NEW DELHI, SEPTEMBER 6—SEPTEMBER 12, 2020, SATURDAY/BHADRA 15—BHADRA 21, 1942

---

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

---

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

---

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं  
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India  
(Other than the Ministry of Defence)

---

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

नई दिल्ली, 20 जून, 2020

का.आ. 750.—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 8 की उप-धारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री नटराजन चन्द्रसेकरन (जन्म तिथि: 2.6.1963) को दिनांक 3.3.2020 से दो वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय बोर्ड में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के पद पर पुनः नामित करती है।

[फा. सं. 1/1/2020—बीओ-1]

एस. आर. मेहर, उप सचिव

पर, “श्री प्रशांत ठाकुर, सक्षम प्राधिकारी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पी. ए. जे. पी. एल.-ऊना ब्रांच पाइपलाइन परियोजना, उत्तरी क्षेत्र पाइपलाइन, ऊना (हिमाचल प्रदेश)” शब्द रखे जाएंगे।

यह अधिसूचना जारी होने की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. आर-11025(11)/19/2018-ओआर-I/ई-27024]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

## MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

New Delhi, the 18<sup>th</sup> August, 2020

**S. O. 756.**—In pursuance of clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of Government of India in Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. 488(E) dated 8<sup>th</sup> February 2017, namely:

In the said notification, in the Schedule, at Sl. No. (i), for the words “Shri Dev Raj Sharma, Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited, PAJPL – Una Branch Pipeline Project, 346, Kamla Kunj, DC-Colony, Una (Himachal Pradesh) – 174303” the words “Shri Prashant Thakur, Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited, PAJPL-Una Branch Pipeline Project, Northern Region Pipeline, Una (Himachal Pradesh)” shall be substituted.

The notification is applicable from the date of issue.

[F. No. R-11025(11)/19/2018-OR-I/E-27024]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.

## कोयला मंत्रालय

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 2020

**का.आ. 757.**—कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. संख्यांक 529, तारीख 16 जुलाई, 2020, जो भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), तारीख 18 जुलाई, 2020 द्वारा प्रकाशित की गई थी, उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित 684.620 हेक्टेयर (लगभग) या 1691.730 एकड़ (लगभग) माप वाली भूमि में और ऐसी भूमि में (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त भूमि कहा गया है) या उस पर के सभी अधिकार, उक्त अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, आत्यंतिक रूप में केन्द्रीय सरकार में निहित हो गए थे;

और, केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है, कि ओडिशा कोल एण्ड पावर लिमिटेड, भूबनेश्वर, ओडिशा (जिसे इसमें इसके पश्चात् सरकारी कंपनी कहा गया है), ऐसे निबंधनों और शर्तों का, जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त अधिरोपित करना ठीक समझे, अनुपालन करने के लिए रजामंद है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि इस प्रकार निहित भूमि का माप 684.620 हेक्टेयर (लगभग) या 1691.730 एकड़ (लगभग) उक्त भूमि में या उस पर के सभी अधिकार तारीख 18 जुलाई, 2020 से केन्द्रीय सरकार में इस

प्रकार निहित बने रहने के बजाए, निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त सरकारी कंपनी में निहित हो जाएंगे, अर्थात् : -

- (1) सरकारी कंपनी उक्त अधिनियम के उपबंधों और अन्य सुसंगत विधियों के अधीन यथा अवधारित प्रतिकर, ब्याज, नुकसानियों आदि से संबंधित और वैसी ही मदों की बाबत सभी संदाय करेगी;
- (2) सरकारी कंपनी द्वारा शर्त (1) के अधीन, संदेय रकमों का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए उक्त अधिनियम की धारा 14 के अधीन एक अधिकरण का गठन किया जाएगा और उक्त अधिकरण और किसी ऐसे अधिकरण की सहायता करने के लिए नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में, उपगत सभी व्यय, सरकारी कंपनी द्वारा वहन किए जाएंगे और इसी प्रकार, निहित उक्त भूमियों में या उस पर के अधिकारों के लिए या उनके संबंध में अपील आदि विधिक कार्यवाहियों की बाबत उपगत सभी व्यय भी सरकारी कंपनी द्वारा वहन किए जाएंगे ;
- (3) सरकारी कंपनी, केन्द्रीय सरकार या उसके पदधारियों की, ऐसे किसी अन्य व्यय के संबंध में क्षतिपूर्ति करेगी, जो इस प्रकार निहित उक्त भूमि में या उस पर के अधिकारों के बारे में, केन्द्रीय सरकार या उसके पदधारियों द्वारा या उनके विरुद्ध किन्हीं कार्यवाहियों के संबंध में आवश्यक हो ;
- (4) सरकारी कंपनी को केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना, उक्त भूमि में इस प्रकार निहित अधिकारों को किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित करने की शक्ति नहीं होगी ; और
- (5) सरकारी कंपनी, ऐसे निदेशों और शर्तों का अनुपालन करेगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, जब कभी आवश्यक हो, उक्त भूमि के विशिष्ट क्षेत्रों के लिए दिए जाएं या अधिरोपित किए जाएं ।

[फा. सं. 43015/13/2019-एलए एण्ड आईआर]

राम शिरोमणि सरोज, उप सचिव

#### MINISTRY OF COAL

New Delhi, the 7<sup>th</sup> September, 2020

**S.O. 757.**—Whereas on the publication of the notification of the Government of India in the Ministry of Coal, number S.O. 529, dated the 16<sup>th</sup> July, 2020, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 18<sup>th</sup> July, 2020, issued under sub-section (1) of section 9 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act), the land measuring 684.620 hectares (approximately) or 1691.730 acres (approximately) and all rights in or over the said land described in the Schedule appended to the said notification (hereinafter referred to as the said land) vested absolutely in the Central Government free from all encumbrances under sub-section (1) of section 10 of the said Act;

And whereas, the Central Government is satisfied that the Odisha Coal and Power Limited, Bhubaneswar, Odisha (hereinafter referred to as the Government Company) is willing to comply with such terms and conditions as the Central Government thinks fit to impose in this behalf;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the said Act, the Central Government hereby directs that the land measuring 684.620 hectares (approximately) or 1691.730 acres (approximately) and all rights in or over the said lands so vested shall with effect from the 18<sup>th</sup> July, 2020 instead of continuing to so vest in the Central Government, shall vest in the Government Company, subject to the following terms and conditions, namely:-

- (1) the Government Company shall make all payments in respect of compensation, interest, damages, etc., and the like, as determined under the provisions of the said Act and other relevant laws ;
- (2) a Tribunal shall be constituted under section 14 of the said Act, for the purpose of determining the amounts payable by the Government Company under condition (1) and all expenditure incurred in connection with any such Tribunal and persons appointed to assist the Tribunal shall be borne by the

Government Company and similarly, all expenditure incurred in respect of all legal proceedings like appeals, etc., for or in connection with the rights, in or over the said land, so vesting, shall also be borne by the Government Company;

- (3) the Government Company shall indemnify the Central Government or its officials against any other expenditure that may be necessary in connection with any proceedings by or against the Central Government or its officials, regarding the rights in or over the said lands so vested;
- (4) the Government Company shall have no power to transfer the said lands to any other persons without the prior approval of the Central Government; and
- (5) the Government Company shall abide by such directions and conditions as may be given or imposed by the Central Government for particular areas of the said lands as and when necessary.

[F. No. 43015/13/ 2019-LA & IR]

RAM SHIROMANI SAROJ, Dy. Secy.

### शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 2020

**का.आ. 758.**—भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), तारीख 10 मई-16 मई, 2020 (साप्ताहिक) में प्रकाशित भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की संख्यांक अधिसूचना का.आ. 410, तारीख 11 मई, 2020, अधिसूचना के हिंदी पाठ में:-

(क) पृष्ठ 1177 पर '(ग) संरक्षित वन भूमि का विवरण' के नीचे की सारणी में,-

- (i) पंक्ति-15 में, क्रम सं. 9 के सामने आंकड़े '44.827' के स्थान पर आंकड़े '43.827' पढ़ें ;
- (ii) पंक्ति-19 में, क्रम सं. 13 के सामने 'भाग' के स्थान पर 'पूर्ण' पढ़ें ;
- (iii) पंक्ति-22 में, क्रम सं. 16 के सामने आंकड़े '4.956' के स्थान पर आंकड़े '4.946' पढ़ें ।

(ख) पृष्ठ 1178 में,

- (i) पंक्ति -3 में, 'ग्राम चकेरी (भाग)' के स्थान पर 'ग्राम पेरोगिया (भाग)' पढ़ें ।
- (ii) पंक्ति-7 में, आंकड़े 'पी-2126 (भाग)' के स्थान पर आंकड़े 'पी-2126 (पूर्ण)' पढ़ें ।

[फा. सं. 43015/8/2019—एलए एण्ड आईआर]

राम शिरोमणि सरोज, उप सचिव

### CORRIGENDUM

New Delhi, the 7th September, 2020

**S.O. 758.**—In the notification of the Government of India, Ministry of Coal number S.O. 410, dated the 11<sup>th</sup> May, 2020 and published in the Gazette of India, Part-II, Section-3, Sub-section (ii), dated the 10<sup>th</sup> May-16<sup>th</sup> May, 2020 (weekly), notification in Hindi version:-

- (a) on page 1177, at below Table '(C) Details of Protected Forest Land: ', -
  - (i) In line, 15, against Sl. No. 9 for figure '44.827, read figure '43.827';
  - (ii) In line, 19, against Sl. No. 13 for 'Part', read 'Full';
  - (iii) In line, 22, against Sl. No. 16 for figure '4.956', read figure '4.946'.
- (b) on page 1178,
  - (i) In line, 3, for 'village Chakeri (Part)', read 'village Parogiya (Part)';
  - (ii) In line, 7, for figure 'P-2126(Part)', read figure 'P-2126(Full)'.

[F. No. 43015/8 /2019-LA&IR]

RAM SHIROMANI SAROJ, Dy. Secy.

**Letter No-OCPL/HGR/LAND/2021/200**

**Date - 06/04/2021**

**TO,**

**The C.G.M (Land),  
IDCO, Bhubaneswar**

**Sub:** Acquisition of Private land measuring an area of Ac. 24.26 in village Sarbahal and Ac. 0.08 in village Manoharpur and Ac. 22.85 in village Laikera, under Hemgir Tahasil in the District of Sundargarh for development of Dip Side Manoharpur Coal Mine.

**Sir,**

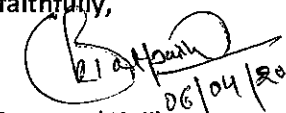
With reference to the subject cited above, I am herewith submitting the acquisition proposal of Private Land measuring an area of Ac. 24.26, Ac. 0.08 and Ac. 22.85 respectively in village Sarbahal, Manoharpur and Laikera under Hemgir Tahasil, in the District of Sundargarh as delineated in the enclosed land plan as per detail land schedule for development of Dip Side Manoharpur Coal Mine.

Since the land is required by us for infrastructure development, we would therefore, request you to kindly initiate the land acquisition proposal before Collector, Sundargarh and make the land available to us at the earliest possible time.

**Encl:**

- 1) Land Schedule
- 2) Land Plan
- 3) Certified Copies of RoRs
- 4) Authorization to file Land Acquisition Proposal.

**Yours faithfully,**

  
**General Manager (Civil)** 06/04/2021

Copy to CEO, OCPL for kind information.

Letter No- OCPL/HGR/LAND/2021/199  
Date - 06/04/2021

TO,

The C.G.M (Land),  
IDCO, Bhubaneswar

Sub: - Alienation of Govt. land measuring an area of Ac. 15.95 in village Sarbahal, Ac. 0.44 in village Ghumudasan, Ac. 0.35 in village Dulinga, Ac. 0.31 in village Manoharpur and Ac. 14.03 in village Laikera, under Hemgir Tahasil in the District of Sundargarh for development of Dip Side Manoharpur Coal Mine.

Sir,

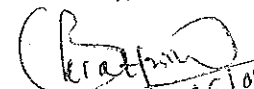
With reference to the subject cited above, I am herewith submitting the acquisition proposal of Private Land measuring an area of Ac. 15.95, Ac. 0.44, Ac. 0.35, Ac. 0.31 and Ac. 14.03 respectively in village Sarbahal, Ghumudasan, Dulinga, Manoharpur and Laikera under Hemgir Tahasil, in the District of Sundargarh as delineated in the enclosed land plan as per detail land schedule for development of Dip Side Manoharpur Coal Mine.

Since the land is required by us for infrastructure development, we would therefore, request you to kindly initiate the alienation proposal before Collector, Sundargarh and make the land available to us at the earliest possible time.

Encl:

- 1) Land Schedule.
- 2) Land Plan.
- 3) Certified Copies of RoRs.
- 4) Authorization to file Land Acquisition Proposal on behalf of OCPL.
- 5) Certificate of Incorporation to OCPL.
- 6) Allotment Order of Department of Energy, Govt. of Odisha in favor of OCPL.
- 7) Allotment Order of Ministry of Steel & Mines Dept., Govt. of Odisha in favor of OCPL.
- 8) Allotment Order of Ministry of Coal, Govt. of India in favor of OCPL.
- 9) Memorandum and Article of Association of OCPL.
- 10) Detailed Project report of Manoharpur and Dip Side Manoharpur Coal Block.

Yours faithfully,

  
General Manager (Civil) 06/04/2021

Copy to CEO, OCPL for kind information.